package. Though control of price of commodities is not within the ambit of the said Rules, the issue of fixing the profit margin limits for consumer articles was referred to the said Committee. The Committee felt that the profit element is a complicated issue and vary from product to product. Hence the issue should appropriately be looked into by the concerned administrative Ministries.

शीतल पेयों पर उत्पाद शुल्क में छूट

876. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष के बजट में कोका कोला और पेप्सी कोला सहित शीतल पेयों पर उत्पाद -शुल्क में छूट दी गई थी,

(ख) यदि हां, तो यह छूट कितनी थी,

(ग) क्या यह सच है कि छूट के पश्चात् कोका कोला और पेप्सी कोला की कीमतों में कमी करने की बजाय उनकी कीमतों में वृद्धि कर दी गई है, और

(घ) सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) और (ख) वित्त मंत्रालय ने सूचित किया है कि 1995-96 के बजट में वातित जल पर उत्पाद शुल्क 50% से घटा कर 40% कर दिया गया है।

(ग) और (घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, जो शीतल पेयों के संबंध में प्रशासकीय मंत्रालय है, ने सूचित किया है कि 1995-96 के बजट में शीतल पेयों पर उत्पाद शुल्क में रियायत की घोषणा के बाद इनके मूल्य कम नहीं हुए हैं। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि उन्होंने शीतल पेय के विनिर्माताओं तथा बोतल भरने वालों के साथ एक बैठक की थी और उन पर दबाव डाला कि वे घोषित की गई शुल्क रियायतों के लाभ उपभोक्ताओं को दें।

MOU Signed by DGFT with Car Manufacturers

877. DR. RANBIR SINGH:
SHRI RAM NATH KOVIND:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Director General of Foreign Trade has recently signed a Memorandum of Understanding with some car manufacturers;

(b) if so, the details of Memorandum of Understanding; and

(c) whether Government have taken any measures to ensure that the sale prices of the proposed cars are within the range of Indian buyers?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) and (b) Yes, Sir. Two Memorandums of Understanding (MOU) one with M/s. DCM-Daswos Motors Ltd., and the other with M/s. Kalyan Motors Company Ltd., have been signed. These MoUs would enable these companies to obtain licences to import assemblies/sub-assemblies in CKD/SKD form. Details regarding levels of indigenisation, setting up of manufacturing facilities, out-flow of foreign exchange on account of such imports and in-flow of foreign exchange on account of equity contribution by the foreign company and exports were incorported in these MoUs.

(c) There is no statutory control on prices of vehicles, including cars. It is expected that with the availability of a wide range of models of cars, market competition will keep a check on prices of new cars.